भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1686

13.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएलआई-ऑटो योजना के लिए बजटीय आवंटन में कमी

1686 **डा. के. लक्ष्मणः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पीएलआई-ऑटो योजना के बजट आवंटन को घटाकर 2,000 करोड़ रुपये किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती के क्या कारण हैं;

(ग) इस कटौती से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माताओं और घटक आपूर्तिकर्ताओं, जो पहले विस्तार के लिए प्रतिबद्ध थे, पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है; और

(घ) हरित विनिर्माण और रोजगार सृजन के इस योजना के मूल लक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) : वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएलआई-ऑटो स्कीम हेतु बजट आवंटन को बजट अनुमान (बीई) ₹2818.85 करोड़ से घटाकर संशोधित अनुमान (आरई) चरण में ₹2,091.26 करोड़ कर दिया गया है। यह कमी स्वीकृत आवेदकों द्वारा प्रोत्साहन दावों के संशोधित अनुमानों के कारण की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त प्रोत्साहन दावे, वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्रमाणित उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों (एएटी) की वास्तविक बिक्री से संबंधित हैं और इनका निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(घ) : स्कीम के उद्देश्यों की सुरक्षा हेतु, भारी उद्योग मंत्रालय स्वीकृत आवेदकों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है तथा प्रोत्साहन दावों के प्रस्तुतिकरण में उन्हें सहयोग प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं।

****